राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9331/2024

मेघराज पुत्र पुरखाराम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 9, जज्जू, पुलिस थाना जज्जू, जिला बीकानेर। (वर्तमान में केन्द्रीय कारागार बीकानेर में बंद) -----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य पी.पी. के माध्यम से ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री जे.एस. चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री प्रदीप चौधरी के साथ।

सुश्री सम्पति चौधरी।

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री नरेन्द्र सिंह चांदावत, पी.पी.

श्री विकास गोदारा और

श्री भोला राम चाहर, शिकायतकर्ता के लिए।

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

18/09/2024

1. याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन कोलायत, जिला बीकानेर में दर्ज एफआईआर संख्या 75/2024 में गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में

लिया गया है, जो आईपीसी की धारा 498 (ए), 306 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित है और इस याचिका के माध्यम से, वह जमानत-बांड पर अपनी स्वतंत्रता की बहाली चाहता है।

2. इससे पहले कि मैं प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करूं, वर्तमान मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताना उचित होगा कि शिकायतकर्ता संतोष भार्गव (मृतक रेखा के पिता) ने 09.04.2024 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी रेखा की शादी वर्ष 2014 में आरोपी मेघराज से हुई थी। शादी के बाद से, उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे और मार रहे थे। शराबी मेघराज एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध में शामिल था। इसके बावजूद, उनकी बेटी ने परिवार के सम्मान की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया और शिकायतकर्ता को इन मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेघराज अक्सर अपनी बेटी को पीटता था और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। 08.04.2024 की रात को मेघराज के भाई ने फोन करके बताया कि रेखा ने आत्महत्या कर ली है। जब वह उसके ससुराल पहुंचा तो उसे संदेह हुआ कि उसकी हत्या की गई है और आत्महत्या का रूप देने के लिए यह घटना रची गई है। मामले की जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

3. सबसे पहले आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि यह शादी के 10 साल बाद पत्नी द्वारा आत्महत्या का मामला है। उसके तीन बच्चे थे। रेखा ने अपनी मर्जी से फांसी लगाकर आत्महत्या की। इस मामले में आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के तत्व संतुष्ट नहीं हैं। यह तर्क दिया गया है कि आईपीसी की धारा 306 लगाने के लिए पुलिस द्वारा जांच में दिया गया कारण यह है कि मेघराज के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसके कारण कथित तौर पर रेखा ने

आत्महत्या की। हालांकि, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि मेघराज ने रेखा की आत्महत्या के लिए सक्रिय रूप से उकसाया था और न ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत अनुमान इस मामले में लागू होता है। प्रस्तुतियाँ समाप्त करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

4. राज्य के विद्वान लोक अभियोजक श्री विकास गोदारा की सहायता से शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आवेदक के विद्वान वकील द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों पर कड़ी आपत्ति जताई है और आवेदक की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की है।

5. बार में उठाए गए तर्कों की सराहना करने के लिए, मैंने अपने उत्सुक विचार और रिकॉर्ड पर उपलब्ध मामले की सावधानीपूर्वक जांच की है।

6. रिकॉर्ड के अवलोकन और प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट होगा कि इस मामले में, शिकायतकर्ता की बेटी रेखा की शादी के 7 साल बाद मृत्यु हो गई और इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत अनुमान लागू नहीं होता है। आरोप-पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के विवाहेतर संबंध में शामिल होने से पति द्वारा उकसाने की पुष्टि होती है।

7. यह देखा गया है कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयानों में, मृतक रेखा के पिता ने याचिकाकर्ता द्वारा उकसाने के किसी विशेष मामले का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि शादी के बाद से, मेघराज रेखा को परेशान और पीट रहा था। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि मेघराज

शराबी था और एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध में शामिल था। उपरोक्त को छोड़कर, याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार के उकसावे के संबंध में कोई कानाफूसी नहीं है।

8. उपरोक्त साक्ष्यों के मद्देनजर, विचारणीय प्रश्न यह है कि "क्या उकसावे के किसी विशिष्ट कृत्य के अभाव में, इन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, याचिकाकर्ता को प्रथम दृष्टया रेखा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला माना जा सकता है"?

9. आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना होगा कि मृतक रेखा ने आत्महत्या की और याचिकाकर्ता ने आत्महत्या के लिए उकसाया। अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि मृतक रेखा के पिता ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयानों में मृतक को किसी भी प्रकार के उकसावे के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है, सिवाय इसके कि शादी के बाद से मेघराज रेखा को परेशान और पीट रहा था। मेघराज शराबी था और एक महिला के साथ अवैध संबंध में भी शामिल था। कथित विवाहेतर संबंध को छोड़कर, जो अवैध और अनैतिक हो सकता है, अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, उकसाया या प्रेरित किया।

10. इस न्यायालय की राय है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतका के पति के अवैध संबंध के बारे में कुछ सबूत हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर कुछ अन्य स्वीकार्य प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव में, आईपीसी की धारा 306 के तत्व, जिसमें महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाना शामिल है, प्रथम दृष्टया

संतुष्ट नहीं पाए जा सकते। विवाहेतर संबंध, अपने आप में या इस तरह से, उकसाने के दायरे में नहीं आते। स्पष्ट करने के लिए, केवल इसलिए कि पति विवाहेतर संबंध में शामिल है और पत्नी के मन में कुछ संदेह है, इसे आईपीसी की धारा 306 के तत्वों को संतुष्ट करने के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। मृतक के मन में संदेह के बीज बोने से अंततः त्रासदी हुई, लेकिन ऐसी घटना प्रथम दृष्टया आरोपित अपराध नहीं बनती। इसलिए, याचिकाकर्ता जमानत के लिए मामला बनाता है।

11. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद; आवेदक के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क विशेष रूप से ऊपर वर्णित तथ्य और यह तथ्य कि आवेदक 08.04.2024 से हिरासत में है; जमानत अस्वीकृति आदेश से पता चलता है कि आवेदक किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है; कि मुकदमे में काफी समय लगने की संभावना है और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, मैं मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस विचार के साथ कि आवेदक के पास अभियोजन पक्ष के मामले पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं और आवेदक को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए, मैं इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक हूं।

12. परिणामस्वरूप, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी-याचिकाकर्ता मेघराज पुत्र पुरखाराम, जिसे पुलिस स्टेशन कोलायत, जिला बीकानेर में दर्ज एफआईआर संख्या 75/2024 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए पर्याप्त राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानत बांड प्रस्तुत करे, जिसमें यह शर्त हो कि वह सुनवाई की

सभी तिथियों पर और जब भी बुलाया जाए, उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि आरोपी, अपनी रिहाई के 7 दिनों के भीतर, और जमानत प्रस्तुत करने वाले दिन, अपने सभी बैंक खातों का विवरण, बैंक और शाखा के नाम के साथ, शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे, और अपने आधार कार्ड की सुपाठ्य प्रति और साथ ही बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की प्रति प्रस्तुत करेंगे, ताकि भविष्य में धारा 446 सीआरपीसी के तहत जुर्माना राशि की वसूली की आवश्यकता होने पर जुर्माना राशि की आसानी से वसूली हो सके।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।